बतचीत के बिन्दू–08

28 और 29 मार्च, 2022 की आम हड़ताल पर।

भारत बिक्री के लिए नहीं है!

हम, जनता, इसकी अनुमति नहीं देंगे!

एलआईसी का निजीकरण न हो

भारत सरकार चालू वित्त वर्ष में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से निजी कारोबार के हाथों में एलआईसी के शेयर बेचना शुरू करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करने की तैयारी कर रही है। सूचीबद्ध करने की सुविधा के लिए वित्त विधेयक 2021–22 के हिस्से के रूप में एलआईसी अधिनियम में आवश्यक कानूनी बदलाव गुप्त रूप से लाए गए हैं। सरकार आईपीओ में विदेशी पूँजी को भाग लेने की अनुमति देने के लिए कुछ और बदलाव लाने पर विचार कर रही है। इस प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली संस्था एलआईसी के शेयरों का विनिवेश चरणबद्ध मरीके से किया जाएगा और इसका मकसद देशी–विदेशी निजी वित्तीय कॉरपोरेट के पक्ष में एलआईसी का पूरी तरह से निजीकरण करना है। सभी ट्रेड यूनियनें आईपीओ का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे इसे निजीकरण की दिशा में पहला कदम और मूलभूत उद्देश्यों के लिए खतरा मानते हैं।

आईपीओ के बारे में खोखले तर्कः

सरकार कुछ झूठी दलीलें देकर आईपीओ प्रक्रिया के जरिए एलआईसी के विनिवेश के कदम को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। सरकार के अनुसार, एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने से अनुशासन आएगा, वित्तीय बाजारों तक पहुँच प्रदान की जाएगी और इसके मूल्य को खुला कर दिया जाएगा। यह कदम इस तरह से बनाई गई संपत्ति में खुदरा निवेशकों को भाग लेने का अवसर भी देगा।

ये तर्क खोखले हैं। एलआईसी एक पारदर्शी और कुशल बोर्ड प्रबन्धित संस्थान है। यह हर तिमाही अपने बारे में सार्वजनिक रुप से खुलासा करती है। यह हर महीने अपने कामकाज की रिपोर्ट भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को प्रस्तुत करता है। इसके खातों को जाँच के लिए संसद में रखा जाता है। यह पारदर्शी कामकाज नहीं तो और क्या है?

जबकि, निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाऐं ज्यादातर गैर–पारदर्शी होती हैं और परिचालन घोटालों से भरी होती हैं, जिससे निवेशकों और ग्राहकों को भारी नुकसान होता है। ये सभी तथ्य समय–समय पर सार्वजनिक होते रहे हैं। और अभी तक कोई भी एलआईसी पर उंगली नहीं उठा सका है और न ही इसकी परिचालन शुद्धता के बारे में सवाल उठा सका है। वास्तव में, निजी क्षेत्र का बड़ा व्यवसाय जानबूझकर ऋण–चूक, जानबूझकर कर–चोरी और विभिन्न अन्य गलत तरीकों के माध्यम से भ्रष्टाचार और कदाचार का पर्याय है। निजी क्षेत्र के बीमा व्यवसाय ज्यादातर अपने पॉलिसीधारकों को धोखा देने के लिए कुख्यात हैं; एलआईसी के साथ तुलना करने पर उनका दावा–निपटान खराब है। अन्य वार्डों में निजी बीमा कंपनियों के दावों की अस्वीकृति एलआईसी की तुलना में बहुत अधिक है।

एलआईसी भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा निवेशक है। यह तर्क हास्यास्पद है कि सूचीबद्ध होने से एलआईसी को बाजार से धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। एलआईसी सालाना 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपये की निवेश योग्य निधि उत्पन्न करता है और इसलिए धन के लिए बाजार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह सामान्य ज्ञान है कि शेयर बाजार में कुल प्रतिभागियों में से केवल 3 फीसद ही खुदरा निवेशक हैं। यह कहना कि सूचीबद्ध करने से खुदरा निवेशकों के लिए मूल्य बढ़ेगा, यह बात सच्चाई से बहुत दूर है। यह अमीरों, विदेशी पूँजी और घरेलू संस्थागत निवेशकों के लिए ही मूल्य और लाभ में वृद्धि करने के काम आएगा। इसका सीधा सा मतलब है अमीरों के लिए मूल्य वृद्धि के लिए हमारे बेहतरीन वित्तीय संस्थानों में से एक को उनके हाथों में सौंपना है।

यह कहना कि सूचीबद्ध करने से पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा होगी, इसका मतलब है कि एलआईसी में इस पहलू की कमी है, जो कि बिलकुल भी सच नहीं है। एलआईसी ने अपने पॉलिसीधारकों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की है। पॉलिसीधारकों के फंड की कुल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, इसका बोनस के रूप में सर्वोत्तम रिटर्न देने का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसने बहुत उच्च सेवा मानक निर्धारित किए हैं। इसका दावा निपटान प्रदर्शन वैश्विक बीमा उद्योग में सबसे अच्छा है। भारत में सम्पूर्ण जीवन बीमा उद्योग में इसकी परिचालन लागत सबसे कम है।

इस प्रकार, बेहतर पारदर्शिता, पॉलिसीधारकों के हितों आदि के तर्क मौजूदा वास्तविकता के सामने पूरी तरह से विफल हो जाते हैं।

एलआईसी एक सुनहरी हंस

एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य नीतिगत धन को सुरक्षा प्रदान करना और देश के औद्योगीकरण के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए बचत जुटाना था।

पिछले 65 वर्षों में, एलआईसी ने सबसे सफल सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान के रूप में उभरने में इन मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को समर्पित किया। यह अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया है। अर्थव्यवस्था का कोई भी ऐसा क्षेत्र खोजना मुश्किल है जहाँ इस महान संस्था के पदचिन्ह न मिले हों। इसने राष्ट्रीय विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसने अर्थव्यवस्था में करीब 36 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। एलआईसी का 82 फीसद से अधिक निवेश सरकारी प्रतिभूतियों और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में है।

एलआईसी ने पिछले 64 वर्षों में अपने शानदार प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों को पूरा किया है। इसने जीवन बीमा के संदेश को देश के दूर–दराज के हिस्सों में फैलाया है। यह देश में सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला ब्रांड बन गया है। 40 करोड़ से अधिक के पॉलिसीधारक आधार के साथ, इसने लाखों भारतीय परिवारों के जीवन को प्रभावित किया है। एलआईसी के प्रबंधन के तहत सम्पत्ति 38 लाख करोड़ रुपये है। यह निवेश योग्य कोष के रूप में सालाना 4–5 लाख करोड़ रुपये पैदा करता है। इसने अपनी स्थापना के बाद से सरकार को 28,695 करोड़ रुपये से अधिक संचयी लाभांश का भुगतान किया है।

एलआईसी आज 23 निजी बीमा कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। 20 साल की प्रतिस्पर्धा के बाद भी, यह प्रीमियम आय में लगभग 66 फीसद और पॉलिसियों की संख्या में 75 फीसद की हिस्सेदारी के साथ बाजार पर हावी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में एलआईसी ने कुल 4.02 लाख करोड़ रुपये (नए व्यवसाय और नवीनीकरण दोनों) की प्रीमियम आय अर्जित की। इसने 2.72 लाख करोड़ रुपये की निवेश आय अर्जित की है। इस विशाल संस्था की वर्ष 2020–21 की कुल शुद्ध आय 6.82 लाख करोड़ रुपये है। इसने इस वर्ष के दौरान 2.1 लाख करोड़ रुपये के दावों का निपटारा किया है। इसने एलआईसी को सेवित पॉलिसियों की संख्या और दावों के निपटान के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा जीवन बीमाकर्ता कम्पनी बना दिया है। वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों में, इसका दुनिया में सबसे अच्छा दावा निपटान रिकॉर्ड है।

विनिवेश का असर

अनुभव बताता है कि विनिवेश अंततः निजीकरण की ओर ले जाता है। विनिवेश में निश्चित रूप से राष्ट्रीय विकास से ध्यान हटाकर शेयरधारकों के मुनाफे को अधिकतम करने पर केन्द्रित होगा। इस प्रक्रिया में एलआईसी के पूरे बिजनेस मॉडल को बदलना होगा। समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक रूप से आवश्यक बीमा की उपेक्षा करने के लिए उच्च प्रीमियम वाले कुलीन व्यवसाय पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

ग्रामीण भारत की कीमत पर शहरी और महानगरीय केन्द्रों पर ही अधिक केन्द्रीयकृत होगा।

अधिकतम मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए पारम्परिक बंदोबस्ती उत्पादों को प्रोत्साहित करने के बजाय शेयरधारकों को बेहतर रिटर्न देने में सक्षम नीतियों के विक्रय की प्रवृत्ति होगी। ऐसी स्थिति देश के सामाजिक और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए धन जुटाने के लिए एक गंभीर खामी पैदा हो जाएगी,

गरीबों को कई बुनियादी सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा जो सरकार एलआईसी द्वारा प्रदान की गई धनराशि के साथ प्रदान करती थी।

सरकार एलआईसी में विदेशी पूँजी की भी अनुमति दे रही है। यह निश्चित रूप से विदेशी पूँजी को घरेलू बचत पर अधिक पहुँच और नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम करेगा जो राष्ट्रीय विकास परियोजना को नुकसान पहुँचाएगा।

एलआईसी निजीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। एलआईसी आईपीओ जो निश्चित रूप से इस महान संस्थान को भविष्य में निजीकरण की ओर ले जाएगा, जो पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डालता है। यह कॉरपोरेट समर्थक और जनविरोधी नवउदारवादी एजेंडे का हिस्सा है, जिसे मोदीनीत भाजपा सरकार द्वारा आक्रामक तरीके से आगे ले जाया जा रहा है।

इसलिए, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि एलआईसी में विनिवेश की दिशा में सरकार के कदम और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्वतंत्रता के हित में इसके निजीकरण का विरोध करें।

28–29 मार्च 2022 को दो दिवसीय आम हड़ताल मोदी सरकार को अपनी कॉरपोरेट समर्थक नीतियों को उलटने के लिए, किसी भी नाम से निजीकरण को रोकने के लिए मजबूर करने के इस संघर्ष का हिस्सा लें।

आइए एकजुट हों और लड़ें!

28–29 मार्च 2022 की आम हड़ताल को शानदार तरीके से सफल बनाऐं!